पूर्ण बेंच

समक्ष एस. एस. संधावालिया, **मुख्य न्यायाधीश,** *प्रेम चंद जैन और डी.एस.तेवतिया, न्यायाधीश*

अमर बीर सिंह और अन्य, ***याचिकाकर्ता,***

बनाम

महा ऋषि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और अन्य,*उत्तरदाता।*

***सिविल रिट सं.* 1979 *का* 2459**

9 मई, 1980।

भारत का संविधान 1950 - *अनुच्छेद* 14 *और* 15 (4) - *शहरी स्कूलों की तुलना में सामान्य ग्रामीण स्कूलों में उम्मीदवार विकलांग - ऐसे उम्मीदवारों को शहरी स्कूलों में शिक्षित* लोगों के साथ समानता देने के लिए उत्थान की मांग की गई - ग्रामीण स्कूलों में शिक्षित उम्मीदवारों के लिए एक चिकित्सा संकाय में सीटें आरक्षित - ऐसे उम्मीदवारों के लिए कोई शर्त नहीं

ग्रामीण क्षेत्रों का निवासी होना चाहिए - इस तरह का आरक्षण - चाहे संवैधानिक रूप से वैध हो।

यह माना गया कि आरक्षण का अंतर्निहित उद्देश्य सामान्य ग्रामीण स्कूलों में शिक्षित छात्रों के विकलांग वर्ग का उत्थान करना है ताकि शहरी स्कूलों में शिक्षित अपने पर्यावरण वरिष्ठों के साथ प्रतिस्पर्धा की कुछ समानता हासिल की जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य द्वारा किया गया वर्गीकरण, जो पूरी तरह से पूर्वोक्त अप्रतिरोध्य और उद्देश्य 1 कारकों पर आधारित है, एक उचित है। वर्गीकरण न तो छात्रों के जन्म स्थान पर दूर-दूर तक निर्भर करता है और न ही उम्मीदवारों या उनके परिवारों के संबंध में निवास की किसी भी स्थिति से जुड़ा हुआ है। एक बार जब यह मान लिया जाता है कि वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत दोनों है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका उन उद्देश्यों से सीधा संबंध है जिन्हें प्राप्त करने की मांग की गई है क्योंकि पिछले वर्षों के अनुभव से पता चला है कि आम ग्रामीण स्कूलों के विकलांग छात्रों को शहरी शिक्षित वर्ग के खिलाफ असमान प्रतिस्पर्धा में चिकित्सा संकायों में प्रवेश पाने से लगभग समाप्त कर दिया गया था। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) की प्रयोज्यता का प्रश्न नहीं उठता है और किया गया वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से टिकाऊ है। जिन छात्रों ने गांवों में स्थित सामान्य ग्रामीण स्कूलों में अध्ययन किया है, वे शहरों और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने वालों से बहुत अलग वर्ग बनाते हैं। शहरी स्कूलों में उपलब्ध विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, शिक्षण कर्मचारियों और इसी तरह की शैक्षिक सुविधाओं और गांवों में आम ग्रामीण स्कूलों में उनकी कमी और कभी-कभी कुल अनुपस्थिति के बीच विशाल अंतर सर्वविदित है। इस प्रकार, ग्रामीण स्कूलों में शिक्षित उम्मीदवारों के लाभ के लिए किया गया आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है। (पैरा 18 और 19)।

(माननीय न्यायमूर्ति पीसी जैन और माननीय श्री जैन की खंडपीठ द्वारा भेजा गया मामला। न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया ने 28 अगस्त, 1979 *को इस रिट याचिका में शामिल कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए एक बड़ी पीठ को सौंप दिया। माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति पीसी जैन और माननीय न्यायमूर्ति डी एस तेवतिया की वृहद पीठ ने अंततः 9 मई, 1980 को रिट याचिका पर निर्णय लिया।*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका *में प्रार्थना की गई है कि:-*

1. परमादेश की एक *रिट जारी की जा सकती है जिसमें यह घोषणा की जाए कि*

अनुलग्नक पी-1 और पी-2 *के तहत* ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण *अवैध*, अधिकारहीन, *अमान्य और असंवैधानिक है और इसलिए प्रतिवादी* 1 से *4* को *इसे लागू करने से रोका जा सकता है;*

2. *उत्तरदाताओं का चयनउपर्युक्त आरक्षण के आधार* पर 5 से 34 *तक का आरक्षण भी गैरकानूनी,* अमान्य और *अमान्य है और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है;*

3. *उत्तरदाता संख्या।* 1 से 4 तक के छात्रों *को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने के लिए निर्देशित किया जा सकता है क्योंकि वे मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश के लिए विधिवत योग्य हैं। उन्हें केवल ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए किए गए आरक्षण के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया है;*

4. *या ऐसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझा जा सकता है, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है।*

5. *प्रतिवादी संख्या 10को अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है।* 1 से 4 *उन्हें याचिकाकर्ताओं को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने का निर्देश देना ताकि याचिकाकर्ता कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम हो सकें। यदि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत नहीं दी गई, तो वे कक्षाओं में भाग लेने के लाभ से वंचित हो जाएंगे और उनके पास व्याख्यान की कमी भी हो सकती है। उस स्थिति में रिट याचिका निरर्थक हो सकती है।*

6. *मामले की अत्यधिक तात्कालिकता को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं के निपटान में कोई समय नहीं है, प्रतिवादियों पर नोटिस की सेवा के संबंध में शर्तों को हटा दिया जा सकता है।*

7. *प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका की लागत दी जा सकती है।*

के.पी. भंडारी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील गोपी चंद और वकील रवि कपूर।

बलवंत सिंह मलिक। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एस. एस. अहलावत, अतिरिक्त ए. जी. हरियाणा .

निर्णय

***एस.एस. संधावालिया,* मुख्य न्यायाधीश**

1. क्या सामान्य ग्रामीण स्कूलों में शिक्षित छात्रों के विकलांग वर्ग को चिकित्सा संकाय में प्रवेश के लिए कुछ सीटों के आरक्षण के माध्यम से असंतुलन को कम करने के लिए शहरी शिक्षित छात्रों की तुलना में कुछ मामूली अधिमान्य उपचार की अनुमति दी जा सकती है, यह महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है जो इस पूर्ण पीठ के समक्ष निर्णय के लिए आता है।

2. यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मुद्दा मुख्य रूप से कानूनी है और आवश्यक रूप से

तर्कसंगतता और संवैधानिकता से संबंधित होगा।

वर्गीकरण में शामिल तथ्यों के मैट्रिक्स को जन्म देने के लिए अनिवार्य रूप से कुछ की आवश्यकता होती है ('विस्तार से नोटिस)। तीनों याचिकाकर्ताओं ने एमडी विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में विधिवत अर्हता प्राप्त की और उसके आधार पर: उक्त विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय में प्रवेश का दावा किया। इस पर प्रवेश के लिए प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, कुल 115 में से 25 सीटें ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, जिन्होंने किसी ऐसे गांव में स्थित सामान्य ग्रामीण स्कूल में 8 वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी, जिसमें कोई नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या टाउन एरिया समिति नहीं थी, इस आरक्षण का दावा करने के लिए, आवेदन के साथ प्रॉस्पेक्टस के परिशिष्ट 'सी' में निर्धारित फॉर्म में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। प्रवेश के लिए तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार, अनुबंध पी 3 के *अनुसार,* याचिकाकर्ताओं के नाम ओपन मेरिट सूची के क्रम संख्या 76, 88 और 89 में दिखाई दिए, लेकिन उन्हें सामान्य ग्रामीण स्कूलों में शिक्षित छात्रों के विकलांग वर्ग के लिए किए गए आरक्षण के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। उनकी ओर से मूल निर्भरता *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य राज्यों पर* थी । *प्रदीप टंडन और अन्य,* (1) ने इस आधार पर कहा कि इससे पहले एमडी विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा किए गए इसी तरह के आरक्षण को कुमारी प्रोमिला जैन आदि में डिवीजन बेंच द्वारा रद्द कर दिया गया था। बहुत। *प्रदीप टंडन के मामले* (सुप्रा) *में फैसले का पालन करके* हरियाणा राज्य और अन्य, (2)।

3.प्रतिवादियों की ओर से दाखिल रिटर्न में तथ्यात्मक स्थिति बिल्कुल भी दूषित नहीं है। हालांकि, श्रेणीबद्ध रुख यह है कि वास्तव में प्रदीप टंडन के मामले में आरक्षण की प्रकृति वर्तमान से पूरी तरह से अलग थी और इसके साथ कोई समानता नहीं है। यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में प्रश्न पूरी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत था और *कुमारी प्रोमिला जैन के मामले* (सुप्रा) में भी यही स्थिति थी जो फिर से उसी अनुच्छेद के दायरे में आती थी। दृढ़ रुख यह है कि यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि यहां लागू आरक्षण ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए है क्योंकि इसकी प्रयोज्यता के लिए ग्रामीण क्षेत्र में न तो निवास की स्थिति है और न ही जन्म की कोई शर्त है। उदाहरण के लिए, यह बताया गया है कि डॉक्टरों, ग्राम सचिवों, कृषि विभाग, बिजली विभाग, सहकारिता विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के बेटे और बच्चे, जिन्होंने सामान्य ग्रामीण स्कूलों में अपनी शिक्षा प्राप्त की है, कई अन्य उम्मीदवारों के साथ आरक्षण के हकदार होंगे जो न तो निवासी हो सकते हैं और न ही ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुए हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 15 (4) की प्रयोज्यता का कोई सवाल नहीं उठेगा और उत्तरदाताओं द्वारा किया गया वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से टिकाऊ है। जिन छात्रों ने गांवों में स्थित सामान्य ग्रामीण स्कूलों में अध्ययन किया है, वे शहरों और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने वालों से बहुत अलग

दावा करते हैं। शहरी स्कूलों में उपलब्ध विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, शिक्षण कर्मचारियों और इसी तरह की शैक्षिक सुविधाओं के बीच विशाल अंतर और गांवों में आम ग्रामीण स्कूलों में उनकी कमी और कभी-कभी कुल अनुपस्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इसके बाद यह पता चला है कि उत्तरदाताओं ने रोहतक, कुरुक्षेत्र, सिरसा, कमल, गुड़गांव और हिसार जिलों में विशेषज्ञ सर्वेक्षण किए हैं और उनकी रिपोर्ट या सिनोप्स को रिटर्न के अनुलग्नक आर. 1/3 से आर. 1/8 के रूप में संलग्न किया गया है। उत्तरदाताओं के अनुसार, उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट सामान्य ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा समान रूप से सामना की गई बाधाओं के स्कोर को सामने लाती है। उक्त रिपोर्ट से, सामने आने वाली बुनियादी बाधाओं को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया जा सकता है- *आर. 1/3* से आर. 1/8 तक :-

1. ग्रामीण स्कूलों में अधिकांश छात्र पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के होते हैं और उनके माता-पिता ज्यादातर मामलों में अशिक्षित होते हैं, वे शहरी क्षेत्रों के बच्चों की तुलना में अपनी स्कूल की उपलब्धियों में नुकसान में होते हैं, जिसमें अधिकांश मामलों में माता-पिता स्वयं अच्छी तरह से शिक्षित होते हैं;

2. शायद ही किसी ग्रामीण स्कूल में गर्मियों में बिजली के पंखे की व्यवस्था होती है और बारिश के मौसम के बाद चरम गर्मी का मौसम ग्रामीण छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष को लगभग छोटा कर देता है और यह कारक उन्हें शहरी स्कूलों के बच्चों की तुलना में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में नुकसान में रखता है जहां शैक्षणिक सत्र अत्यधिक गर्मी या बरसात के मौसम से बाधित नहीं होता है।

रोहतक जिले में झज्जर और बहादुरगढ़ उपमंडलों के सैकड़ों स्कूल हर साल बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

इन दिनों के दौरान शिक्षा प्रदान करना लगभग असंभव हो जाता है।

1. हरियाणा राज्य में अब तक कार्यान्वित किए गए विकास कार्यक्रम ग्रामीण जीवन को अच्छे शिक्षकों के लिए आकर्षक नहीं बना पाए हैं और इसलिए वे किसी भी ग्रामीण स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी स्कूलों में शैक्षिक सुविधाओं में बहुत असमानता है और ऐसी स्थिति में ग्रामीण स्कूलों में शैक्षणिक उपलब्धियों की **तुलना शहरी स्कूलों की उपलब्धियों के साथ गुणात्मक रूप से** नहीं की जा सकती है।

2. रोहतक जिले के कई ग्रामीण माध्यमिक/उच्च विद्यालयों में विज्ञान परास्नातक और गणित स्नातकोत्तर उपलब्ध नहीं हैं । नतीजतन, ग्रामीण स्कूलों के छात्र पिछड़ जाते हैं।

विज्ञान और गणित के विषयों में पीछे हैं जिनका वर्तमान तकनीकी युग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण स्कूलों में छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पाने में सक्षम बनाने के लिए, मौजूदा स्थिति उन्हें एक बड़े नुकसान में डालती है।

3. अधिकांश ग्रामीण स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हैं। इसलिए, ग्रामीण स्कूलों में छात्र विज्ञान में उच्च पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जीवन में पढ़ने की रुचि या प्रयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में विफल रहते हैं।

4. सभी अच्छे मान्यता प्राप्त निजी स्कूल और पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, यदि कोई हो, शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। पूरे रोहतक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई मोड-I /पब्लिक स्कूल नहीं है।

5. आम तौर पर शिक्षक शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और ग्रामीण स्कूलों में अपने कर्तव्यों में भाग लेने के लिए बस यात्रियों के रूप में जाते हैं; बस समय पर वहां पहुंचें और तुरंत बाद इसे छोड़ दें।

स्कूल के निर्धारित घंटे। इस प्रकार उनके पास शाम को या स्कूल के घंटों से बाहर अपने छात्रों से मिलने का समय नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण स्कूल में छात्रों का पाठ्येतर जीवन खराब रहता है और इससे उनके व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

6. सैकड़ों प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में पर्याप्त भवन, पर्याप्त खेल के मैदान, पीने के पानी की सुविधा नहीं है।

और ऐसी स्थिति ग्रामीण स्कूलों में छात्रों को एक अनुकूल शैक्षिक वातावरण देने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है।

7. शहरी स्कूलों की तुलना में ग्रामीण स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत स्पष्ट रूप से कम है। ग्रामीण बच्चों को शहरी स्कूलों के उनके प्रति-भागों के लिए उपलब्ध आधी सुविधाएं और अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। नतीजा यह है कि उनकी तुलना शहरी स्कूलों के छात्रों के साथ नहीं की जा सकती है।

8. शहरी छात्रों को उनके दरवाजे पर शैक्षिक सुविधाएं मिलती हैं जबकि ग्रामीण छात्रों को स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना 4 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली केवल 46 प्रतिशत आबादी के पास अपने गांवों में मिडिल स्कूल की सुविधा है। गांवों में हाई स्कूल की सुविधा केवल 33 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए उपलब्ध है।

9. शहरी क्षेत्रों में कई मॉडल/पब्लिक स्कूल हैं। वे प्रीनर्सरी, एलकेजी और केजी कक्षाओं में तीन साल की उम्र के छात्रों को प्रवेश देते हैं। इन स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों को शुरू से ही शैक्षिक माहौल मिलता है और उनकी नींव इन कक्षाओं में बनती है जबकि ग्रामीण बच्चों को ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

4.राज्य का यह दृष्टिकोण है कि उपर्युक्त स्पष्ट असमानताओं को दूर करने के लिए किसी भी ग्रामीण स्कूल में शिक्षित छात्रों के विकलांग वर्ग के पक्ष में आरक्षण के साथ-साथ प्रवेश के वर्तमान नियमों को तैयार करना आवश्यक हो गया है। यह अन्यथा पिछले वर्षों के अनुभव से कहा गया था, जो इंगित करता है कि ग्रामीण स्कूलों से कोई शिक्षा प्राप्त करने वाला शायद ही कोई उम्मीदवार 1978-79 और 1979-80 के शैक्षणिक सत्रों के दौरान चिकित्सा संकाय के लिए ओपन मेरिट श्रेणी में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक वर्ष इस श्रेणी के केवल पांच उम्मीदवारों को ओपन मेरिट श्रेणी के आधार पर प्रवेश मिल सकता है और उनका अनुपात प्रत्येक वर्ष में केवल 6 प्रतिशत हो जाएगा, हालांकि वे हरियाणा राज्य की आबादी के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तरदाताओं के अनुसार, ऐसी स्थिति स्पष्ट रूप से दो वर्गों के बीच लगातार बनी असमानता को दूर करने के उपायों की मांग करती है, जो अन्यथा कायम रहती।

5. यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्यव्यापी सर्वेक्षण से उभरने वाली स्पष्ट असमानताओं के संबंध में उत्तरदाताओं के रुख को दूषित करने के लिए कोई प्रतिकृति दायर नहीं की गई है।

6. इससे पहले कि कोई इसमें शामिल मुद्दों की जांच करे, यह सवाल बहुत ही दहलीज पर उठता है कि क्या ये प्रदीप टंडन के मामले में बाध्यकारी मिसाल के दायरे में आते हैं /अनिवार्य रूप से सिद्धांत या मिसाल पर किसी भी चर्चा में प्रवेश करने से पहले इसे पहले सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि इस न्यायालय के भीतर यह स्पष्ट रूप से निरर्थक अभ्यास होगा यदि उपरोक्त निर्णय क्षेत्र को कवर करता है। इस प्रश्न के साथ कुमारी प्रोमिया जैन के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले की प्रयोज्यता भी *है,* जो संक्षेप में केवल *प्रदीप टंडन के मामले का अनुसरण करता है।*

7.अब उनके *प्रदीप टंडन के मामले* में उत्तर प्रदेश राज्य में मेडिकल कॉलेजों के लिए किए गए आरक्षण पर विचार किया गया.part जो निम्नलिखित शर्तों में था -

(x) आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिससे वे संबंधित हैं कि वे और उनके परिवार ग्रामीण क्षेत्रों या पहाड़ी जिलों या उत्तराखंड मंडल में से एक के स्थायी निवासी हैं, जैसा भी मामला हो, और उन्होंने उस क्षेत्र में अपनी शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा लिया है।

इससे पहले यह मुद्दा सुभाष चंद्रा बनाम भारत मामले में खंडपीठ द्वारा विचारार्थ लाया गया था । *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* (3) और दलीप कुमार *बनाम* दलीप कुमार *उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य,* (3-ए) और बाद में प्रदीप टंडन बनाम भारत मामले में पूर्ण पीठ द्वारा । *उत्तर प्रदेश राज्य* (4) अब उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें वर्गीकरण का मूल न केवल उम्मीदवारों के जन्म और निवास स्थान पर बल्कि उनके परिवारों के जन्म स्थान पर भी टिका हुआ <u>था, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी होने की आवश्यकता थी।</u>

1.एआईआर 1973 सभी। 295.

(3-ए) ए.आई.आर. 1973 सभी। 592.

2. एआईआर 1975 सभी। 1.

उत्तराखंड मंडल के पहाड़ी जिलों में से एक। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 15 पूरी तरह से इस तरह के भेदभाव को रोकता है, सिवाय इसके खंड (4) में निर्धारित अपवाद की संकीर्ण सीमाओं के भीतर। दिलीप कुमार बनाम *दिलीप कुमार* मामले *में खंडपीठ के फैसले का सीधा संदर्भ।उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* (सुप्रा) यह दर्शाते हैं कि इसमें मामले को संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत मुख्य रूप से देखा गया था, यदि पूरी तरह से नहीं, और विद्वान न्यायाधीशों ने स्वयं देखा कि निर्देशों के लिए मुख्य चुनौती यह थी कि वे संविधान के अनुच्छेद 15 (4) से प्रभावित थे । यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि नागरिकों के वर्ग का निर्धारण, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होने के रूप में उचित नहीं था और इसलिए, आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15 (4) का उल्लंघन था। इसी तरह, *सुभाष चंद्र* बनाम *भारत मामले में फैसले का विश्लेषण।उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,* ■ (सुप्रा), राज्य यह इंगित करेगा कि इस मुद्दे की पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 15 (1), (2), (3) और (4) के संदर्भ में जांच की गई थी।.

8. अब यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उपर्युक्त दो खंडपीठ के निर्णयों के स्पष्ट टकराव के कारण प्रदीप टंडन बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय मामले में पूर्ण पीठ को संदर्भित करना आवश्यक हो गया था । *उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य* (5). चूंकि दोनों फैसलों ने इस मामले को अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 15 के आलोक में देखा था, इसलिए यह अपरिहार्य था और वास्तव में पूर्ण पीठ के फैसले के संदर्भ से पता चलेगा कि तर्क फिर से बदल गया, मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 15 और खंड (4) की प्रयोज्यता या अन्यथा।.

9.अब *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* राज्यों में। *प्रदीप टंडन* [और अन्य] (सुप्रा), अन्य के बीच अपील- प्रदीप टंडन बनाम अन्य मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई थी । *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,* (सुप्रा), और *सुभाष चंद्र* वी। *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* (सुप्रा)।

मुख्य न्यायाधीश रे द्वारा दिए गए फैसले के अवलोकन के अलावा, *प्रदीप टंडन के मामले* में पीठ की ओर से बोलने से शायद ही कोई संदेह होता है कि जिस मुद्दे को उठाया गया था, वह मुख्य रूप से और सीधे संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत था और इसके खंड (4) की प्रयोज्यता या अन्यथा था । विद्वान मुख्य न्यायाधीश निष्कर्ष पर पहुंचे :-

आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15 (4> के अपेक्षित परीक्षण को पूरा नहीं करता है और यह रिपोर्ट के पैरा 29 और 30 में निम्नलिखित शब्दों में निष्कर्ष से प्रकट होता है: –

> " सीटों के आरक्षण के निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि आवेदन पत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों से आरक्षित सीट के लिए एक उम्मीदवार को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे वह संबंधित था कि वह ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ था और वहां एक स्थायी घर था, और वहां रह रहा है, या वह भारत में पैदा हुआ था और उसके माता-पिता और अभिभावक अभी भी वहां रह रहे हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। वहाँ। *ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म की घटना को मूल योग्यता बनाया जाता है। जन्म स्थान के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करेगा*।

यह स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य की है कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए है। राज्य ने स्थापित किया है कि पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्रों के लोग नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि *प्रदीप टंडन के मामले* (सुप्रा) का फैसला संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से किया गया था।.

10.अब *कुमारी प्रोमिला जैन के मामले* (सुप्रा) पर आते हुए, यह याद करने योग्य है कि वर्तमान आरक्षण से पहले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक ने 1978 में मेडिकल कॉलेज, रोहतक में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के प्रवेश के लिए 25 सीटें आरक्षित की थीं। इस आरक्षण के लिए पात्र होने के लिए, तीन शर्तें निर्धारित की गई थीं, जिन्हें इसके बाद *विस्तार* से उद्धृत किया जाएगा। यह केवल यह आरक्षण था जो डिवीजन बेंच के समक्ष विचार के लिए आया था और विद्वान न्यायाधीशों ने इस संदर्भ में विचार व्यक्त किया कि *प्रदीप टंडन* के मामले में की गई टिप्पणियां उनके समक्ष मामले पर पूरी ताकत के साथ लागू होती हैं और उसी के बाद उक्त आरक्षण को रद्द कर दिया जाता है। उक्त निर्णय दिए जाने के बाद यह स्पष्ट रूप से था कि अब हरियाणा राज्य ने अपने दम पर वर्तमान आरक्षण बनाया है जिसे यहां चुनौती दी जा रही है। अंतर को उजागर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पहले किए गए आरक्षण और सरकार द्वारा किए गए वर्तमान आरक्षण को बाहर लाने के उद्देश्य से लागू करना सबसे अच्छा है।

इसमें सार्थक अंतर और साथ ही दृष्टांतों की प्रयोज्यता :-

विश्वविद्यालय द्वारा पहले आरक्षण

1. उम्मीदवार के माता-पिता का नाम गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए।

2. माता-पिता को गांव में खेती या संबद्ध गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।

3. उम्मीदवारों को किसी भी गांव में स्थित स्कूल से कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जिसमें नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र या शहर क्षेत्र समिति नहीं है।

(ii)

ग्रामीण क्षेत्रों से उम्मीदवार की पात्रता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड ों का पालन किया जाएगा -

एक उम्मीदवार को किसी भी गांव में स्थित एक सामान्य ग्रामीण स्कूल में 8 वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें कोई नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र या नगर क्षेत्र समिति नहीं है।

इस उद्देश्य के लिए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसे अप्पेन में देखा जा सकता है- डि C क्स

यह उपरोक्त से स्पष्ट होगा। उस भाषा और आरक्षण दोनों में विषय-वस्तु, पहले और आक्षेपित सामग्री हैं- वास्तव में और वास्तव में एक दूसरे से मौलिक रूप से अलग। पहले का आरक्षण पूरी तरह से उम्मीदवारों के जन्म स्थान और माता-पिता के निवास पर निहित था, जिन्हें गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता होना था और इस प्रकार उनकी आवश्यक पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करना था। फिर न केवल उम्मीदवार को, बल्कि उसके माता-पिता को खेती या इसकी संबद्ध गतिविधियों से संबंधित गांव में व्यवसाय की कसौटी को पूरा करना पड़ा। दूसरी ओर, वर्तमान आरक्षण ऐसी किसी भी शर्त या सीमा से पूरी तरह से रहित है। इसके लिए न तो जन्म स्थान के संदर्भ की आवश्यकता होती है और न ही माता-पिता के निवास स्थान की निरंतरता की आवश्यकता होती है, न ही उम्मीदवार के परिवार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कोई प्रासंगिकता होती है। अनिवार्य रूप से, यह इस प्रकार है कि वर्तमान आरक्षण अपनी प्रकृति और दायरे दोनों में पहले के आरक्षण से भौतिक रूप से अलग जमीन पर टिका हुआ है।

11.अब *प्रदीप टंडन के मामले में और* कुमारी *प्रोमिया जैन के मामले* में भी आरक्षण का वर्गीकरण और दायरा (जब इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों की सामग्री के साथ पढ़ा जाता है) ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा हुए व्यक्तियों और उनके परिवारों के निवासी होने के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रकृति के लिए विस्तारित किया गया है। वर्तमान आरक्षण में यह दूर-दूर तक नहीं है। वास्तव में, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता बलपूर्वक यह बताने में सक्षम थे कि यह बात शायद सच होगी और उन्होंने सही तर्क दिया कि यहां आरक्षण ग्रामीण आबादी के लिए एक व्यापक नहीं है, बल्कि केवल उन लोगों के लिए है जो असुविधाजनक, खराब आवास वाले और खराब क्षमता वाले सामान्य ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने में निहित बाधा का सामना करते हैं। इसका एक उदाहरण यह था कि स्वास्थ्य, कृषि, बिजली या राजस्व विभागों में ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात रहते हुए शहरी अभिजात वर्ग से संबंधित एक सैनिक भी अपने बच्चों के लिए आरक्षण का दावा करने में सक्षम होगा, अगर वे अपनी पोस्टिंग के स्थान पर सामान्य ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर, एक समृद्ध ग्रामीण आधारित परिवार के बच्चे आरक्षण के तहत नहीं आएंगे यदि उन्होंने शहरी क्षेत्रों में अच्छे स्कूलों में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आरक्षण ग्रामीण आबादी के लिए एक पूर्ण नहीं है और न ही शहरी जन्म या शहरी निवासी आबादी के खिलाफ भेदभावपूर्ण है, बल्कि आम ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की बाधा से पीड़ित होने के तर्कसंगत कारक से निहित है, जो उत्तरदाता-राज्य के अनुसार विज्ञान और गणित के संबंध में कोई मेल नहीं खाता है। शहरी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा और जो चिकित्सा संकाय में प्रवेश के लिए आवश्यक आधार है।

12. यह स्पष्ट है कि *प्रदीप टंडन के मामले और कुमारी प्रोमिया जैन* के मामले को, उसी के बाद, पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्निहित सिद्धांत पर तय किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में उक्त प्रावधान दूर-दूर तक आकर्षित नहीं है। लिखित बयान और उसकी दलीलों के साथ-साथ अदालत में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के समान रूप से वर्गीकृत तर्क में प्रतिवादी-राज्य का निष्पक्ष रुख यह है कि यहां अनुच्छेद 15 को दूर-दूर तक लागू नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादियों की ओर से मामले को अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से आराम करने की मांग की गई है और यह बलपूर्वक तर्क दिया गया है कि यह इस समानता खंड के अपेक्षित परीक्षणों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। यह स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है। जैसा कि पहले देखा गया है, लागू आरक्षण अब जन्म स्थान या निवास की आवश्यकता और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के लिए कम से कम प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, निर्धारित सिद्धांत और

उपरोक्त दो मामलों में चर्चा हो सकती है, लेकिन वर्तमान में बहुत कम प्रासंगिकता है ।

13.इसलिए ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उत्तर प्रदेश राज्य में किए गए आरक्षण का हिस्सा थी जो प्रदीप टंडन के मामले में विचार के लिए गिर गया था।*यह महत्वपूर्ण है कि इसमें या सुभाष चंद्र बनाम* सुभाष चंद्र *मामले* में खंडपीठ द्वारा दर्ज किए गए निर्णयों में एक भी टिप्पणी नहीं *है।उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* (सुप्रा) और *दिलीप कुमार* वी। *उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (सुप्रा) के साथ-साथ* प्रदीप टंडन के मामले में *उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप* द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया है कि आम ग्रामीण स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के पिछड़ेपन को वर्गीकरण का आधार नहीं बनाया जा सकता है। सभी तीन निर्णय पूरी तरह से मौन हैं और वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 15 (1) से (4) पर पूरा प्रश्न बदल गया है, और यह पहलू बिल्कुल भी विचार के लिए नहीं आया। वास्तव में, शायद यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा के पिछड़ेपन के आधार पर वर्गीकरण में उनके लॉर्डशिप ने कम से कम दुर्बलता या अमान्यता नहीं पाई और इसलिए, या तो इसे मौन रूप से स्वीकार कर लिया या किसी भी मामले में इसे पूरी तरह से विचार से नजरअंदाज कर दिया। इसलिए, *प्रदीप टंडन का मामला* यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आम ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता तर्कसंगत वर्गीकरण के लिए एक मानदंड नहीं हो सकती है।.

14. इस पहलू पर अपनी बात समाप्त करने के लिए, मैं मानता हूं कि *प्रदीप टंडन* का मामला और *कुमारी प्रोमिला जैन का मामला* पूरी तरह से अलग-अलग हैं और लागू किए गए आरक्षण की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य और इससे पहले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई नींव से पूरी तरह और मौलिक रूप से अलग है।.

15.उपर्युक्त मिसालों की गैर-प्रयोज्यता के बारे में आधार को साफ करने के बाद, इस मामले की अब सैद्धांतिक रूप से जांच की जा सकती है। अनिवार्य रूप से यह प्रश्न उठता है कि आरक्षण का उद्देश्य और उद्देश्य क्या है? यदि वह उद्देश्य वैध और प्रशंसनीय है, तो जो कुछ भी शेष है, वह यह निर्धारित करना है कि क्या आरक्षण द्वारा किया गया वर्गीकरण तर्कसंगतता का है और उस उद्देश्य के साथ कोई संबंध है, जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है? उत्तरदाता-राज्य का निष्पक्ष दृष्टिकोण यह है कि आरक्षण का अंतर्निहित उद्देश्य सामान्य ग्रामीण स्कूलों में शिक्षित छात्रों के विकलांग वर्ग का उत्थान करना है ताकि शहरी स्कूलों में शिक्षित अपने पर्यावरण वरिष्ठों के साथ प्रतिस्पर्धा की कुछ समानता सुनिश्चित की जा सके। एक तरह से यह प्रयास आम ग्रामीण स्कूलों में शिक्षित ों की खराब गुणवत्ता से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न असमानता को दूर करने और इस विकलांगता या विकलांगता को स्थानिक बनने से रोकने के लिए है। जैसा कि लिखित वक्तव्य में कहा गया

है, मेडिकल कॉलेजों में सीटों को समाज के सभी वर्गों के बीच निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से वितरित करने की मांग की जाती है।

16.आरक्षण में निहित एक द्वितीयक और सहायक उद्देश्य यह था कि विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक प्रस्तुत किया गया था कि बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के प्रावधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक दीर्घकालिक उद्देश्य भी था। यह सामान्य मामला है कि ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक चिकित्सा सहायता से वंचित कर दिया गया है और कोई भी योग्य डॉक्टर इन क्षेत्रों में प्रैक्टिस स्थापित करने और यहां तक कि ऐसे स्थानों पर सरकारी सेवा में पोस्टिंग स्वीकार करने के लिए लौटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार और विश्वविद्यालयों को मेडिकल छात्रों द्वारा बांड के निष्पादन का प्रावधान करना पड़ता है ताकि उन्हें विधिवत योग्य होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि, यह कहा गया था कि इन बॉन्डों को प्रदर्शन की तुलना में उल्लंघन में अधिक सम्मानित किया जाता है और कभी-कभी एक योग्य छात्र के लिए दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की कठिन शर्तों को लेने के बजाय बॉन्ड के तहत जुर्माना भरना लाभदायक होता है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा कुछ हद तक व्यवहार्यता के साथ तर्क दिया गया था कि आम ग्रामीण स्कूलों में शिक्षित छात्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने का बोझ उठाने की संभावना पूरी तरह से शहरी उन्मुख छात्रों की तुलना में बहुत अधिक और बड़ी थी।

17.मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सामाजिक न्याय करने और सामान्य ग्रामीण स्कूलों में शिक्षित छात्रों को अच्छे शहरी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले उनके अधिक पसंदीदा प्रति-भागों के साथ बराबरी पर लाने का उपरोक्त उद्देश्य न केवल वैध है, बल्कि प्रशंसनीय भी है। इसलिए, अगला प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आरक्षण के लिए किया गया वर्गीकरण उचित और टिकाऊ है? यह फिर से बहुत संदेह की बात नहीं लगती है। यह वर्गीकरण सामान्य ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा के पेटेंट पिछड़ेपन के उद्देश्य मानदंड पर आधारित है और विशेष रूप से उसमें विज्ञान शिक्षा की, जो अनिवार्य रूप से वह आधार है जिस पर चिकित्सा संकाय में बाद के शिक्षण को आराम दिया जाना है। यह, वर्तमान सामग्री पर, तथ्यों की यथार्थवादी मान्यता से ज्यादा कुछ नहीं लगता है जो स्पष्ट हैं और चेहरे पर घूरते हैं। हालांकि, प्रतिवादी-राज्य न केवल आंखों के सामने स्पष्ट मामलों पर निर्भर करता है, बल्कि

डेटा पर विशेषज्ञ रूप से एकत्र और जांच की गई और उससे निकाला गया अपरिहार्य निष्कर्ष। इस संदर्भ में, अनुलग्नक आर-एल/3 से आर-एल/8 को पहले ही कुछ विस्तार से संदर्भित किया जा चुका है और इस रिकॉर्ड पर तथ्यों और उसमें प्राप्त निष्कर्षों पर संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में इस बात पर थोड़ा विवाद होगा कि आम ग्रामीण स्कूलों में अधिकांश छात्र ऐसी स्थिति में निहित सभी बाधाओं के साथ पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होंगे। अच्छी इमारतों की अनुपस्थिति और कुछ मामलों में शायद ही कोई इमारत और बिजली के पंखे आदि की व्यवस्था न होने के परिणामस्वरूप शैक्षणिक मौसम गर्मी की अत्यधिक कठोरता और बरसात के मौसम और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है। राज्य का यह रुख है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर की परिस्थितियां इन सामान्य ग्रामीण स्कूलों में अच्छे शिक्षकों को आकषत करने के अनुकूल नहीं हैं और प्रदान की जाने वाली शिक्षा में अपरिहार्य गुणात्मक गिरावट आई है। विशेष रूप से, अच्छे विज्ञान शिक्षकों की कमी और कभी-कभी विज्ञान शिक्षकों की पूर्ण अनुपस्थिति और यहां तक कि अंग्रेजी के शिक्षण की बुनियादी कमी, जो चिकित्सा शिक्षा के लिए मुख्य माध्यम है, को उजागर किया जाता है, अंतर्निहित बाधाओं को उजागर किया जाता है, जैसे कि आम ग्रामीण स्कूलों के साथ-साथ विज्ञान प्रयोगशालाओं में पुस्तकालयों की अनुपस्थिति और यहां तक कि जहां विज्ञान प्रदान किया जाता है। आवश्यक उपकरण आदि उपलब्ध कराने में विफलता फिर से रिकॉर्ड के मामले हैं। तब यह कहा गया है कि कई मामलों में जो शिक्षक उपलब्ध हैं वे शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं और समय पर स्कूलों में पहुंचते हैं और समापन समय पर चले जाते हैं और इस प्रकार किसी भी सार्थक छात्र-शिक्षक संबंध या पाठ्येतर गतिविधियों के पर्यवेक्षण से इनकार करते हैं। यह सब इस तथ्य से अच्छी तरह से साबित होता है कि शहरी स्कूलों की तुलना में आम ग्रामीण स्कूलों का पास प्रतिशत भी स्पष्ट रूप से कम है। अंत में, यह बताया गया है कि यहां तक कि आम ग्रामीण स्कूलों की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध नहीं है और कई मामलों में छात्रों को केवल 4 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और फिर इसका लाभ उठाने के लिए वहां से लौटना पड़ता है।

18.उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य द्वारा किया गया वर्गीकरण पूरी तरह से पूर्वोक्त अनूठा और उद्देश्यपूर्ण कारकों पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा सकता है जो यह दर्शाता हो कि इस तरह के वर्गीकरण की अनुमति नहीं है। तर्क या कानून। यह दोहराव और प्रकाश डालता है कि यहां यह वर्गीकरण छात्रों के जन्म स्थान पर दूर-दूर तक नहीं टिका है और न ही उम्मीदवारों या उनके परिवारों के संबंध में निवास की किसी भी स्थिति से जुड़ा हुआ है।

19. एक बार जब यह मान लिया जाता है कि वर्गीकरण < 1 दोनों उद्देश्यपूर्ण हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका उन वस्तुओं के साथ सीधा संबंध है जिन्हें प्राप्त करने की मांग की गई है। उत्तरदाता का यह रुख है कि पिछले अनुभव से पता चला था कि शहरी शिक्षित वर्ग के खिलाफ असमान प्रतिस्पर्धा में सामान्य ग्रामीण स्कूलों के विकलांग छात्रों को चिकित्सा संकाय में प्रवेश पाने से लगभग समाप्त कर दिया गया था। 1978-79 के शैक्षणिक सत्र के दौरान सामान्य ग्रामीण स्कूलों के छात्रों की श्रेणी से केवल पांच उम्मीदवार चिकित्सा संकाय में प्रवेश के लिए खुली मेरिट सूची में ग्रेड बना सके। यह इस स्वीकार की गई स्थिति के बावजूद था कि वे मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित हरियाणा राज्य में ऐसे छात्रों की भारी संख्या से संबंधित थे। यह कोई अकेली घटना नहीं थी और 1979-80 के अगले शैक्षणिक वर्ष में फिर से इस विकलांग वर्ग के केवल पांच छात्रों को चिकित्सा संकाय में प्रवेश मिल सका। राज्य का रुख यह है कि यह अनुपात प्रत्येक वर्ष में केवल छह प्रतिशत आता है, हालांकि यह वर्ग हरियाणा में ग्रामीण आधारित समाज के प्रमुख हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार इस विकलांग वर्ग के लिए 25 सीटों के आरक्षण का सीधा प्रभाव है और इसका सामान्य ग्रामीण स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के असंतुलन को समान करने के उद्देश्य से एक पेटेंट संबंध है।

20. सिद्धांत और वर्गीकरण की तार्किक और कानूनी आवश्यकताओं पर डेक को साफ करने के बाद, अब कोई भी मिसाल का विज्ञापन कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम न्यायालय ने स्वयं शैक्षिक बाधाओं के आधार पर किए गए वर्गीकरण को इतनी बार स्पष्ट रूप से बरकरार रखा है कि वर्तमान उन मामलों के अनुपात से पूरी तरह से संरक्षित होगा। वास्तव में उनके लॉर्डशिप ने इस सिद्धांत को वर्तमान मामले में आवश्यक क्षेत्रों से कहीं अधिक क्षेत्रों में विस्तारित किया है।

21. *कुमारी चित्रा घोष और एक अन्य* वी। *भारत संघ और अन्य* (7), मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली में सीटों के आरक्षण को निम्नलिखित श्रेणियों के पक्ष में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करने के रूप में जोरदार चुनौती दी गई थी: -
लगभग से.मी

1. केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों के बेटे/बेटियां जिनमें पंजीकृत विस्थापित व्यक्ति शामिल हैं;

(7) AIR 1970 S.C. 35.

उनके संबंधित क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रायोजित:-

1. हिमाचल प्रदेश (ii) त्रिपुरा (iii) मणिपुर (iv) नागा हिल्स (ग) एनईएफए (vi) अंडमान।

2. विदेश स्थित भारतीय मिशनों में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बेटे/बेटियां।

3. सांस्कृतिक विद्वान।

4. कोलंबो योजना विद्वान।

5. थाईलैंड के विद्वान।

6. जम्मू और कश्मीर राज्य विद्वान।

ग्रोवर, जे. ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए पहले स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 दूर-दूर तक आकर्षित नहीं था और न ही अनुच्छेद 29 (2) चुनौती देने वालों को किसी भी सहायता का था (रिपोर्ट का पैरा नंबर 7)। उन्होंने अनुच्छेद 14 की कसौटी पर उपरोक्त आरक्षण को बरकरार रखा और कहा कि इन सभी मामलों में एक वर्गीकरण समझदार भिन्नता पर आधारित था जो उन्हें सामान्य समूह से या उस समूह से अलग करता था जिससे अपीलकर्ता संबंधित थे। इस मामले के उद्देश्य के लिए विशेष महत्व श्रेणियों (सी), (डी) और (एच) के पक्ष में आरक्षण को बरकरार रखना है और फैसले के विश्लेषण से पता चलेगा कि यहां आरक्षण को मूल रूप से शैक्षिक बाधाओं पर बरकरार रखा गया था, जो इन वर्गों में से प्रत्येक के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ा था। यह देखा गया कि दिल्ली के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार उन क्षेत्रों से आते हैं जहां शैक्षिक सुविधाएं तुलनात्मक रूप से पिछड़ी हुई हैं और इसलिए, इन क्षेत्रों से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को ऐसा करने के लिए कुछ सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मोटे तौर पर, जम्मू और कश्मीर राज्य के छात्रों के संबंध में भी यही विचार सामने आए। विशेष रूप से, विदेशों में भारतीय मिशनों में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में, इन व्यक्तियों के बच्चों को उनकी शैक्षिक सुविधाओं के संबंध में विशेष कठिनाई और बाधाएं झेलनी पड़ीं जिन्हें वर्गीकरण के आधार पर बरकरार रखा गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि उम्मीदवारों द्वारा सामना की जाने वाली शैक्षिक बाधाएं असंतुलन को बराबर करने के लिए वर्गीकरण के लिए एक उपयुक्त मानदंड है। इस निर्णय की ऊँची एड़ी पर बारीकी से अनुसरण करते हुए कानून की निंदा की गई थी-

शेलेट जे., *डी. एन. चंचला* वी. *मैसूर राज्य और अन्य,* (8)। यह फिर से मेडिकल कॉलेजों में रक्षा कामकों, पूर्व रक्षा कर्मियों के बच्चों के साथ-साथ राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए आरक्षण से संबंधित था। उद्देश्य और वस्तु दोनों के संबंध में और वर्गीकरण के लिए समझदार भिन्नता के संबंध में, इसे निम्नानुसार रखा गया था: –

> "लेकिन एक समान रूप से निष्पक्ष और न्यायसंगत सिद्धांत यह भी होगा जो उन लोगों के उचित अनुपात में प्रवेश सुनिश्चित करता है जो विकलांग हैं और जो, लेकिन उन्हें दी गई अधिमान्य उपचार के लिए, उन लोगों के खिलाफ कोई मौका नहीं देंगे जो इतने विकलांग नहीं हैं और इसलिए, एक बेहतर स्थिति में हैं। अनुच्छेद 15(4) में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अधिमान्य रूप से अधिमान्य व्यवहार किया जा सकता है क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को इसकी आवश्यकता है, ताकि समय के साथ वे समाज के अधिक उन्नत वर्गों के साथ समान स्थिति में खड़े हों। यह किसी भी तरह से अनुचित नहीं होगा यदि उस सिद्धांत को उन लोगों पर भी लागू किया जाए जो विकलांग हैं लेकिन अनुच्छेद 15 (4) के तहत नहीं आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सिद्धांत पर रक्षा कामकों और भूतपूर्व रक्षा कामकों के बच्चों के लिए आरक्षण को बरकरार रखा गया है। इस तरह के आरक्षण का मानदंड यह है कि रक्षा बलों में सेवारत या जिन्होंने इस तरह सेवा की है, वे अपने बच्चों को शिक्षा देने में नुकसान में हैं क्योंकि उन्हें कठिन स्थानों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए रहना पड़ता है, जहां कहीं और उपलब्ध सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और उपलब्ध नहीं हैं। हमारे विचार में उस सिद्धांत को राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों तक विस्तारित करना अनुचित नहीं है, जो मुक्ति संघर्ष में उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप जीवन में अस्थिर हो गए; कुछ मामलों में आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए, और इसलिए, अपने बच्चों को शिक्षा का वह वर्ग उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं थे जो उन्हें उन लोगों के बच्चों के साथ उचित प्रतिस्पर्धा में रखेगा जो उस नुकसान से पीड़ित नहीं थे। यदि ऐसा है, तो यह माना जाना चाहिए कि 'राजनीतिक पीड़ित' की परिभाषा न केवल ऐसे पीड़ितों के बच्चों को बाकी लोगों से अलग करती है, बल्कि इस तरह के वर्गीकरण का नियमों के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है जो सीटों के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है........................।

(8) एआईआर 1971 एस.सी.

शेलट, जे की उपर्युक्त समापन टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि आरक्षण को बनाए रखने का औचित्य यह था कि जिस अजीब स्थिति में रक्षा कामकों और पूर्व रक्षा कामकों के बच्चों के साथ-साथ राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को रखा गया था, उन्हें लगातार कुछ शैक्षिक बाधाओं और कमियों का सामना करना पड़ रहा था जिन्हें समान किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में भी यही स्थिति प्रतीत होती है।. , -

22. कुमारी चित्रा घोष और अन्य तथा डीएन चंचला के मामलों *(सुप्रा) के अनुपात का सामना करते हुए* श्री भंडारी को यह तर्क देने के लिए धक्का दिया गया कि रक्षा सैनिकों, राजनीतिक पीड़ितों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, विदेश में तैनात कर्मचारियों आदि के पक्ष में आरक्षण इन वर्गों के प्रति भुगतान किए जाने वाले कृतज्ञता के ऋण के भावनात्मक आधार पर अधिक आधारित था, न कि किसी अन्य पर। इस तरह के विचार के लिए प्रस्तुतीकरण पर केवल ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, वर्गीकरण की संवैधानिक योजना में पूरी तरह से अप्रासंगिक है। हम इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं कि उनके लॉर्डशिप द्वारा कानून की स्पष्ट व्याख्या की गई इस कथित चमक को यह कहते हुए कि इन सभी मामलों के पक्ष में आरक्षण किसी और चीज पर निर्भर नहीं था, बल्कि इस तथ्य पर निर्भर करता है कि ऐसे छात्रों को कुछ शैक्षिक बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कर्मचारियों के खतरों से अविभाज्य हैं। ये शैक्षिक बाधाएं और खतरे हैं जो उन्हें अपने शैक्षिक वरिष्ठों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ या कम से कम असमान बनाते हैं और उनके पक्ष में आरक्षण का उद्देश्य परिस्थितिजन्य कारकों द्वारा बनाए गए असंतुलन को ठीक करना है। एक बार ऐसा होने के बाद, वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से राजदूतों और वरिष्ठ रैंकिंग रक्षा कर्मियों के बच्चों के मामलों की तुलना में उस नियम के भीतर अधिक है।

23.मामला सीधे तौर पर सुखविंदर कौर *बनाम* डिवीजन बेंच के फैसले का है *।हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य,* (9), जो अन्य शब्दों के साथ-साथ चिकित्सा संकाय के लिए सीटों के आरक्षण का मामला था, निम्नलिखित शर्तों में -

(t)

(ङ) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों से मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है /

डिवीजन बेंच ने सोचा कि यह मामला इतना स्पष्ट और उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से कवर किया गया है कि किसी भी बड़े विस्तार की आवश्यकता नहीं है और निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला: –

> 24. दूसरी बात यह है कि 12 सीटों के आरक्षण के संबंध में यथा संशोधित प्रॉस्पेक्टस के पैरा 1 की धारा (ई) भेदभावपूर्ण है। जहां तक इसका संबंध है, यह कहना पर्याप्त होगा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षण है। यह आरक्षण अनुचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जो आमतौर पर ऐसे स्कूलों में जाते हैं, वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से

---

(9) AIR 1974 H.P. 35.

गरीब हैं और वे शहरी क्षेत्रों से आने वाले अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं और इसलिए, आरक्षण वैध है।

यह स्पष्ट है कि सिद्धांत के अलावा, उदाहरण की धारा पूरी तरह से उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए दृढ़ रुख की सहायता में बहती है।

25.एक बार जब यह मान लिया जाता है कि इसे सम्मिलित करने का उद्देश्य या उद्देश्य वैध और प्रशंसनीय है और वर्गीकरण एक समझदार भिन्नता पर आधारित है, तो यह अच्छी तरह से तय प्रतीत होता है कि यह न्यायालयों के लिए वस्तु की वांछनीयता पर निर्णय लेने या वर्गीकरण के लिए नींव के गणितीय मूल्यांकन में प्रवेश करने का काम नहीं है। ऐसी स्थिति में, न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी-राज्य स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि कठिनाई और असमानता की एक विशेष स्थिति में किसका उत्थान और समानता करना है और किसे सहायता प्रदान करनी है। अधिकारियों को बढ़ाना अनावश्यक है। *जम्मू और कश्मीर राज्य* में *त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य* (10)।

संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए चंद्रचूड़, जे. ने कहा, 'एस>

"इसलिए, न्यायिक जांच केवल इस विचार तक विस्तारित हो सकती है कि क्या वर्गीकरण उचित आधार पर टिका हुआ है और क्या इसका उद्देश्य के साथ संबंध है। यह वर्गीकरण के आधार का एक अच्छा या गणितीय मूल्यांकन शुरू करने तक विस्तारित नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह की जांच की अनुमति दी जाती है तो अदालतों के लिए यह खुला होगा कि वे किसी विशेष उद्देश्य को वर्गीकृत करने की आवश्यकता या प्राप्त करने की वांछनीयता पर विधायिका या नियम बनाने वाले प्राधिकरण के लिए अपने स्वयं के फैसले को प्रतिस्थापित करें।

हाल ही में पथुम्मा और अन्य *मामलों में सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस नियम* की निंदा की गई है। *केरल राज्य और अन्य* (11) निम्नलिखित शब्दों में हैं -

" यह भी स्पष्ट है कि वर्गीकरण करने में, विधायिका से एक अमूर्त समरूपता प्रदान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्गों को अनुभव और आसपास की परिस्थितियों द्वारा निर्धारित समाज की आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बस इतना आवश्यक है कि वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम या भ्रामक नहीं होना चाहिए।

26.जैसा कि शुरू से ही देखा गया है, याचिकाकर्ताओं के रुख की आधारशिला *प्रदीप टंडन के मामले* (सुप्रा) में फैसले पर उसकी निर्भरता थी। इससे पूरी तरह से सीख लेते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री केपी भंडारी ने यह तर्क देने की मांग की थी कि लागू किया गया आरक्षण बहुसंख्यक आबादी के लिए था और इसलिए, यह आवश्यक रूप से बुरा था। यह विवाद स्पष्ट रूप से इस धारणा पर आधारित है कि प्रदीप टंडन के मामले का तथ्यात्मक आधार या अनुपात यहां आकर्षित होगा, जिस बिंदु पर पहले ही विस्तार से चर्चा की जा

(10) AIR 1974 S.C. 1.

चुकी है। यह स्पष्ट है कि यहां आरक्षण की आबादी के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है और न ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास या जन्म स्थान की योग्यता पर टिका हुआ है। इसलिए, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक आबादी का कोई सवाल नहीं उठता है और बहुमत या जनसंख्या के सिद्धांत पर आधारित तर्क दूर-दूर तक आकर्षित नहीं होता है। यहां आरक्षण पूरी तरह से सुविधाहीन, कम आवास वाले और कम क्षमता वाले सामान्य ग्रामीण स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के यथार्थवादी मूल्यांकन और उन बाधाओं पर आधारित है जो छात्रों को अनिवार्य रूप से भुगतना पड़ता है।

27. श्री भंडारी ने तब तर्क दिया था कि केवल सामान्य ग्रामीण स्कूलों में माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा का आधार निर्धारित शर्त मनमानी है और इसलिए इस कारण से आरक्षण को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह तर्क फिर से वर्गीकरण के गणितीय या वैज्ञानिक मूल्यांकन को शुरू करने के पेटेंट भ्रम से ग्रस्त है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम *जम्मू और कश्मीर राज्य में बाध्यकारी मिसाल द्वारा न्यायालयों के लिए निषिद्ध है* । *त्रिलोकी नाथ* खोसा और *अन्य* (सुप्रा)। यहां तक कि सामान्य ग्रामीण स्कूलों में मध्य कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने की तर्कसंगतता को सरकार द्वारा सही और बलपूर्वक इंगित किया गया है।

काफी व्यवहार्यता के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता सीखा। यह बताया गया है कि जब तक छात्र सामान्य ग्रामीण स्कूलों में मध्य कक्षा तक पहुंचता है, तब तक प्री-मेडिकल परीक्षा के लिए उसकी शिक्षा के लिए बुनियादी आधार तैयार किया जाता है जो चिकित्सा संकाय में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम है। इसलिए, सामान्य ग्रामीण स्कूलों में आठ साल के अध्ययन की बाधा, उसके बाद उच्च शिक्षा को आत्मसात करने के लिए छात्र के दृष्टिकोण और क्षमता दोनों को निर्धारित करती है। यह भी बताया गया कि हरियाणा में मौजूदा परिस्थितियों के विशिष्ट संदर्भ में, ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश हाई स्कूल विज्ञान विषयों में अध्ययन की आवश्यक सुविधाओं से वंचित थे, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा संकाय के इच्छुक सामान्य ग्रामीण स्कूलों के मध्य कक्षा के छात्रों को बड़े पैमाने पर विज्ञान उन्मुख शहरी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए मजबूर किया गया था और इस प्रकार उन्हें कठिन कार्य में धकेल दिया गया था। जन्मजात रूप से बेहतर फायदे रखने वाले अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा|

28.दलीलों से कहीं आगे और रिकॉर्ड से दूर की यात्रा करते हुए, श्री केपी भंडारी ने वर्ष 1979 के लिए हरियाणा के जनसंपर्क निदेशक द्वारा प्रकाशित एक ब्रोशर का हवाला देने का प्रयास किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का बहुत विकास हुआ है और परिणामस्वरूप अब आम ग्रामीण स्कूलों के छात्रों को कोई महत्व देना उचित नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विवाद यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसमें शिक्षण की समान और शायद अधिक सुविधाओं से लैस सुविधाएं हैं। यह आम ग्रामीण स्कूलों की संख्या या संख्या नहीं है जो यहां समस्या के मूल में है, बल्कि इसमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा की सामग्री और गुणवत्ता है। श्री भंडारी द्वारा यहां उठाया गया विवाद केवल आम ग्रामीण स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता की बुनियादी बाधाओं को उजागर करता है।

29.इसी संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया था कि आम ग्रामीण स्कूलों में अध्ययन की कथित बाधा वैध नहीं है क्योंकि इसमें भी छात्रों को एक ही पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है और वे बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक ही परीक्षा देते हैं। यह विवाद पेटेंट भ्रम से ग्रस्त है। बाधा पाठ्यक्रम या ली जाने वाली परीक्षा की प्रकृति में भिन्नता के कारण नहीं है, बल्कि आम ग्रामीण स्कूलों में छात्रों को प्रदान की जाने वाली और विस्तारित शिक्षा की सामग्री और गुणवत्ता में है, जो अधिक अनुकूल रूप से स्थित और अच्छी तरह से संचालित शहरी स्कूलों की तुलना में है। इसलिए पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की पहचान की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

30.दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सही कहा था कि चिकित्सा शिक्षा का माध्यम आम तौर पर अंग्रेजी है जबकि आम ग्रामीण स्कूलों में, अंग्रेजी भाषा कभी-कभी बिल्कुल नहीं सिखाई जाती है। यदि ऐसा है, तो इसका शिक्षण बाद के चरण में शुरू होता है और शिक्षकों द्वारा इस भाषा को पढ़ाने के लिए इतना अयोग्य सिखाया जाता है कि जिस माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जानी है, वह छात्रों में कमजोर हो जाता है। यह स्थिति तब तक भी मजबूत हो जाती है जब तक छात्र मध्य कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है और कई मामलों में सामान्य ग्रामीण स्कूलों में इस मानक तक के छात्रों को अंग्रेजी भाषा का बहुत कम या कोई ज्ञान नहीं होता है या यदि कोई हो, तो यह इतना अल्पविकसित होगा कि उसके बाद एक बुनियादी बाधा पेश की जाए।

31.श्री भंडारी ने बार-बार यह तर्क देने का प्रयास किया था कि यहां आरक्षण एक ऐसे वर्ग के पक्ष में है जिसे गणितीय रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा नहीं कहा जा सकता है। उनका तर्क केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और उसके खंड (4) के आयात के संदर्भ में प्रासंगिक है। मैं पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि वर्तमान मामला अनुच्छेद 15 के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए उठाए गए विवाद की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है।.

32.उपर्युक्त विस्तृत चर्चा के आलोक में, मेरा सुविचारित विचार है कि लागू किया गया आरक्षण किसी भी असंवैधानिकता से ग्रस्त नहीं है और इसलिए, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। रिट याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। उठाए गए कठिन सवालों को देखते हुए, मैं याचिकाकर्ताओं पर लागत का बोझ डालने से इनकार कर दूंगा।

प्रेम चंद जैन, *न्यायाधीश*— मैं सहमत हूं।

डी. एस. तेवतिया, *न्यायाधीश* - मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा